

अब आइआइएम रांची में सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक करेंगे नेतृत्व और क्षमता वृद्धि

पहले बैच का प्रशिक्षण

कार्यक्रम शुरू,

राज्य भर से प्रधानाध्यापकों के कुल पांच बैच होंगे

कुमार गौरव● रांची

आइआइएम रांची में राज्य के 405 आदर्श विद्यालय (माडल स्कूल) के 80 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में किया गया है। राज्य भर के माडल स्कूलों से प्रधानाध्यापकों के पांच बैच होंगे। वे अगले तीन वर्षों में तीन चरणों में नेतृत्व और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के दौर से गुजरेंगे। बता दें कि इसे लेकर 27 सितंबर 2022 को झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जेर्इपीसी) और आइआइएम रांची के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व और क्षमता वृद्धि के लिए संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रणनीतिक योजना, डिजिटल साक्षरता, समुदाय और हितधारकों की व्यस्तता, छात्रों के सीखने और विकास और समूहों में काम करने जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

शिक्षा विभाग की सराहनीय है पहल

आइआइएम रांची को विश्व स्तर पर उन्मुख और स्थानीय रूप से उत्तरदायी संस्थान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माडल स्कूल प्रधानाध्यापकों के कौशल को बढ़ाने के लिए पहल सराहनीय है। प्रतिभागियों के लिए यह कार्यक्रम नई चीजें सीखने और क्षमता वृद्धि का सशक्त माध्यम है। जिसका लाभ विभिन्न छात्र-छात्राओं को भी मिलेगा। - प्रो दीपक कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, आइआइएम रांची।



दूसरे चरण का निर्णय 13 फरवरी को

फिलहाल प्रायोगिक तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में प्रशिक्षण के बाद दूसरे चरण के लिए 325 नए विद्यालयों को चिह्नित करने की योजना है। इसे लेकर 13 फरवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।



- आकाश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची।

दूसरे चरण में प्रखंड व पंचायत स्तर पर दिया जाएगा प्रशिक्षण

बताया गया कि पहले चरण में 80 विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देने के बाद प्रखंड स्तर पर चिह्नित किए गए 325 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। उम्मीद है कि 13 फरवरी को होने वाली बैठक में

इस दिशा में निर्णय लिया जाएगा। ताकि इस कार्यक्रम से जिला के अलावे प्रखंड व पंचायत स्तर के विद्यालयों को भी जोड़ा जाए। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि प्रबंधन के अभाव में राज्य के कई सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन व अन्य कार्य बाधित होता है। जिसे दुरुस्त

करने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई की समुचित व्यवस्था अमल में लाने के लिए भी यह प्रायोगिक तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिसका लाभ आगामी दिनों सरकारी विद्यालयों में देखने को मिलेगा।

आइआइएम रांची के फैकल्टी कर रहे संचालन : आइआइएम रांची के फैकल्टी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समझौता ज्ञापन में आइआइएम रांची द्वारा प्रभाव मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से

दल का गठन कर दिया गया है। यह दल हरेक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखेगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय के सचिव (झारखण्ड सरकार) के रवि कुमार, आईएएस निदेशक (जेर्इपीसी) किरण कुमार पासी ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से पूरा करने और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण के बाद

सीखे गए पाठ को अमल में लाने का दिशा निर्देश जारी किया है। के रवि कुमार ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम एम्बेडेड प्रौद्योगिकी के उपयोग की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की भूमिका और एनईपी के साथ वर्तमान शिक्षा प्रणाली को जोड़े जाने पर बल दिया है।